भारत का भू-राजनीतिक दृष्टिकोण

सुजन चिनॉय

पूर्व राजदूत एवं महानिदेशक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली।
ईमेल: dg.idsa@nic.in

भारत की विदेश नीति गतिशील है और धर्म (कर्तव्य) तथा वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार) के विशिष्ट भारतीय सभ्यतागत परिवेश पर आधारित है। भारत के बारे में यह दावा निश्चय ही पूरी तरह प्रमाणित कहा जा सकता है। भारत उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम विभाजन को पाटने की क्षमता के साथ वैश्विक दक्षिण की एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। शांति बनाए रखने, युद्धों को रोकने या संघर्षों को शीघ्र समाप्त करने में बहुपक्षीय आदेश की विफलता के कारण मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी और मिनी-पार्श्व समूहों के माध्यम से बहु-संरेखण और बचाव की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। इसके स्पष्ट दोषों के बावजूद, एक नई वैश्विक व्यवस्था को व्यवस्थित करना आवश्यक नहीं है। एक मौलिक पुनर्व्यवस्था से, अभी तक अनदेखे पैमाने पर युद्ध और तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। अनिश्चितताएं जारी रहने के बावजूद, भारत 2025 में अपनी बाहरी गतिविधियों में अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करेगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र और ब्रेटन वुड्स द्वारा प्रस्तुत बहुपक्षीय व्यवस्था, शक्ति संतुलन में बदलाव की उभरती आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई है। वैश्विक समुदाय आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गतिरोध का सामना कर रहा है, जिसमें प्रमुख शक्तियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। शांति बनाए रखने, युद्धों को रोकने या संघर्षों को शीघ्र समाप्त करने में बहुपक्षीय आदेश की विफलता ने मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी और मिनी-पार्श्व समूहों के माध्यम से बहु-संरेखण और बचाव की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। वैश्वीकरण 2.0 में, क्षेत्रीय और मध्य शक्तियां रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ मुद्दा-आधारित

साझेदारी के माध्यम से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रही हैं।

भारत, एक जिम्मेदार प्रमुख शक्ति के सभी गुणों से संपन्न होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, इसे शांति स्थापना अभियानों में योगदान के साथ-साथ दुनिया भर के देशों को महामारी के दौरान वैक्सीन सहायता के लिए सम्मान मिला है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ, भारत कई लोगों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं- (1) तीव्र तथा समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक सूचकांकों तथा महिला-पुरुष समानता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, (2) संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की रक्षा तथा सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, एक स्थिर परिधि बनाए रखना, सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना तथा भारत के दूरदराज के हिस्सों में विकास को बढ़ावा देना और (3) भारत की उत्पादकता तथा विनिर्माण क्षमताओं में सुधार करने और भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में खुद को बेहतर ढंग से एकीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में भागीदार देशों के साथ सहयोग करना।

यह दृष्टिकोण भारत के उच्च विकास पथ को सुविधाजनक बनाने के लिए तीन अलग-अलग स्तरों- आंतरिक, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आम सहमति विकसित करने पर आधारित है। भारत की विदेश नीति के कई सहायक पहलू, जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शामिल करने के लिए घरेलू आयोजनों का उपयोग, जैसा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में स्पष्ट है, इसकी पड़ोसी प्रथम की नीति और इसकी वैश्विक पहल, जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, तालमेल, अभिसरण और सद्भाव बनाने के लिए अपने सभ्यतागत आवेग से प्रवाहित होती हैं।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता उसके बाहरी जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह कई प्रमुख संघर्षों और विरोधाभासों के साथ मेल खाता है। 2023 तक, यूक्रेन में चले लंबे युद्ध की राजनीति, महामारी की उत्पत्ति से आगे निकल गई है जिसने जी20 प्रक्रिया को बर्बाद करने का खतरा पैदा कर दिया। 2020 में गलवान में हुई खूनी घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन एक-दूसरे के खिलाफ थे। इसके अलावा अक्टूबर, 2023 में इजराइल पर हमास के हमलों और उसके प्रतिशोध के साथ गाजा को कठोर दंड मिला। सभी बाधाओं के बावजूद, भारत ने एक सर्वसम्मत दस्तावेज के साथ जी20 की अध्यक्षता सफलतापूर्वक संपन्न की, जिसने असंभावित खिलाड़ियों को आर्थिक विकास और संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करने के लिए एक साझा मंच पर ला दिया। भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान प्रमुख विकासात्मक चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान वापस लाने में सफल रहा। भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा

BRICS 2024 RUSSIA

> सबसे पहले, स्वतंत्र प्रकृति के मंचों को मजबूत और विस्तारित करना है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में विकल्पों को व्यापक बनाकर और उन पर अनावश्यक निर्भरता को कम करना है, जिनसे लाभ मिल सकता है। वास्तव में ये वही मुद्दे हैं, जहां ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के लिए एक बदलाव ला सकता है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ब्रिक्स आउटरीच सत्र में

प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की है।

कोई भी यह दावा कर सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति बहुत प्रभावशाली है, उनकी व्यक्तिगत ऊर्जा और दूरदर्शिता से प्रेरित है, और धर्म (कर्तव्य) तथा वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार) के विशिष्ट भारतीय सभ्यतागत परिवेश पर आधारित है। भारत उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम विभाजन को दूर करने की क्षमता के साथ वैश्विक दक्षिण की एक विश्वसनीय आवाज के रूप में उभरा है। क्रमशः जुलाई और सितंबर, 2024 में मास्को और कीव की प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं ने एक ऐसे देश के रूप में भारत की छवि को रेखांकित किया है जो शांति के लिए खड़ा है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा के दौरान उनका संदेश एक समान था, कि यह युद्ध का युग नहीं है, समाधान युद्ध के मैदान में नहीं पाया जा सकता है, और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

वास्तव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वास्तव में किंत्सुगी क्षण प्रदान किया है। यदि यूक्रेन और गाजा में लंबे युद्धों को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है, तो भू-राजनीतिक दरारें समय के साथ ठीक हो सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हमारे समय की तत्काल चुनौतियों, विशेष रूप से आर्थिक सुधार और जलवायु कार्रवाई पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। कहावत है कि भारत का ज्ञान सोने की उस नस की तरह है जो वैश्विक सर्वसम्मति के किंत्सुगी से होकर गुजरती है, जो इसे और अधिक लचीला बनाती है।

2024 ने कई मोर्चों पर भारत की ताकत की परीक्षा ली है। सीमा क्षेत्रों में कुछ घर्षण बिंदुओं पर चीन के साथ मतभेद बरकरार रहे, जबकि विदेश मंत्रालयों और सशस्त्र बलों के स्तर पर बातचीत जारी रही। अंततः, भारत के धैर्य, दृढ़ता और दृढ़ रुख से, बातचीत में और जमीनी स्थिति दोनों में स्थिति में बदलाव आया। जून 2020 में गलवान में हुई घटना से पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बहाल करने का सफल समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सशस्त्र बल अब बनी नई समझ का जायजा लेंगे और चरण-दर-चरण तरीके से उनके कार्यान्वयन की पुष्टि करेंगे। उन्हें मौजूदा प्रोटोकॉल और विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) की समीक्षा करने और उन कमजोरियों को दूर करने का भी अवसर मिलेगा जिनके कारण झड़पें हुईं। सभी बाधाओं के बावजूद चीन के साथ गतिरोध को दूर करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता एक और संकेत है कि जब विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की हिमायत की बात आती है तो भारत भी 'बातचीत पर चलने' में सक्षम है।

स्पष्ट रूप से, तनाव में कमी और यथास्थिति की बहाली ने कजान में हालिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया बैठक का मार्ग प्रशस्त किया। भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत की बहाली से दोनों पक्षों द्वारा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव फिर से शुरू करने के लिए अगले कदमों पर काम करने की संभावना भी खुल गई है। कई मुद्दों में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान, पत्रकारों की तैनाती, पर्यटन तथा उद्यमियों के लिए वीजा व्यवस्था और अधिक मौलिक रूप से भारत के आत्मनिर्भर भारत निर्माण में चीनी प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की भविष्य की भूमिका का सवाल शामिल है।

G20 भारत 2023 INDIA

भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, ईसीएसडब्ल्यूजी ने जलवायु और पर्यावरण के मामलों पर सफलतापूर्वक आम सहमति बनाई। भारत की अध्यक्षता में अब तक की सबसे लंबी वार्ताओं में से एक, जिसकी सफलता दर 95% पर सहमति थी।

वसुधैव कुटुम्बकम्
एक पृथ्वी • एक परिवार • एक भविष्य

पाकिस्तान की आतंकवाद से दूर रहने की अनिच्छा के कारण पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध स्थिर और प्रतिकूल बने हुए हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनावों ने क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय खोल दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इसकी बहाली की मांग करने वाले एक प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद इतिहास में दर्ज कर दिया गया है।

यदि पाकिस्तान आतंकवाद का उपयोग देश की नीति के साधन के रूप में करने से बचता है, तो इस भावना को अर्थ देना अभी भी संभव है कि भारत और पाकिस्तान को अतीत को दफनाना चाहिए और अच्छे पड़ोसियों के रूप में एक साथ रहना चाहिए। भले ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' की दृढ़ नीति अपनाई है और बातचीत की बहाली को पाकिस्तान के व्यवहार में बदलाव से जोड़ा है, इसने पाकिस्तान के लिए भारत और दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर बेहतर नियति का एहसास करने का दरवाजा भी खुला रखा है।

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का उद्देश्य व्यापक क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। समय के साथ पड़ोसी देशों में परिवर्तन अपरिहार्य है जो उनकी परिस्थितियों से प्रेरित विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता का परिणाम हैं। वे नई और अक्सर अप्रत्याशित चुनौतियां सामने लाएंगे जिनसे उचित तरीके से निपटना होगा।

अक्टूबर, 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्ज़ू की भारत यात्रा के बाद मालदीव के साथ भारत के संबंध फिर से बेहतर स्थिति में आ गए हैं। मालदीव और विस्तारित पड़ोस में अन्य जगहों पर, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण के लिए भारतीय विकल्प, अन्य विकल्पों की तुलना में जोर पकड़ रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल चिंता का कारण है, विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और कट्टरपंथ तथा आगे सीमा पार फैलाव की संभावना। भारत की संवेदनशीलताओं पर ध्यान देना बांग्लादेश के हित में है, जिसमें अवैध प्रवास और पूर्वोत्तर में भारत के सामने आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भी शामिल हैं।

सितंबर, 2024 में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' में अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी के 'उज्ज्वल वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक मानव-केंद्रित दृष्टिकोण' पर जोर देने से उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर अधिक आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बहुपक्षीय संरचनाओं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अव्यवस्था, तर्कसंगत नहीं है। वर्चस्व की राजनीति को आज छोटे से छोटे राष्ट्र भी खारिज कर रहे हैं। मनमानी और जबरदस्ती के लिए प्रतिरोध का निर्माण आवश्यक है, लेकिन यह राष्ट्रों को विकासात्मक लक्ष्यों से भटकाता है।

इसके स्पष्ट दोषों के बावजूद, एक नई वैश्विक व्यवस्था को व्यवस्थित करना आवश्यक नहीं है। एक मौलिक पुनर्व्यवस्था से अभी तक अनदेखे पैमाने पर युद्ध और तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। यह विजेताओं और पराजितों के एक नए समूह को जन्म दे सकता है, जैसा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय हुआ था। यदि दुनिया संयुक्त राष्ट्र और उससे संबद्ध बहुपक्षीय संस्थानों में वास्तविक सुधारों के लिए भारत के आह्वान पर ध्यान दे, तो मौजूदा नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (आरबीआईओ) को अधिक स्वीकार्यता मिल सकती है और यह समकालीन चुनौतियों का सामना करने में अधिक प्रभावी बन सकती है।

संयुक्त राज्य अमरीका में नए राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रम्प का निर्वाचन भारत के लिए नए अवसर और कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छा तालमेल है, जो दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिए अच्छा संकेत है। राष्ट्रपति ट्रम्प के पिछले कार्यकाल को देखते हुए, आतंकवाद, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यवधान सहित प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों पर दोनों देशों के बीच एकरूपता है। इस अभिसरण के और अधिक गहरा होने की संभावना है। दूसरी ओर, भारत को अपने निर्यात पर शुल्क लगाने और अमरीकी उत्पादों के लिए शुल्क कम करने की मांग पर किसी भी नए फोकस को सावधानी से टालना होगा। एच1बी वीज़ा और सख्त अमरीकी आव्रजन नीतियों के सवाल पर कुछ हंगामा होना तय है। सशस्त्र बलों और रक्षा सहयोग के बीच संयुक्त अभ्यास अच्छी तरह से समेकित प्रतीत होता है और रणनीतिक साझेदारी के लिए आधार प्रदान करता रहेगा। यदि राष्ट्रपति ट्रम्प यूक्रेन और गाजा में युद्ध समाप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो यह भारत को प्रतिस्पर्धी दलों के सामने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' को उचित ठहराने के बोझ से मुक्त कर देगा।

अनिश्चितताएं जारी रहने के बावजूद, भारत अपनी बाहरी गतिविधियों में अधिक आत्मविश्वास के साथ 2025 में प्रवेश करेगा। भारत की गतिशील और व्यावहारिक विदेश नीति वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते कद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख रणनीतिक साझेदारों, विशेषकर अमरीका के साथ मिलकर काम करना, जबकि पड़ोसियों, विशेषकर चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना, इस नीति के केंद्र में है। ❑

(लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं)